भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 68
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

आरसीएस-उड़ान की भूमिका

***68 श्री राधेश्याम राठिया:**
डॉ. हेमांग जोशी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में छत्तीसगढ़, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश सहित राज्यवार किफायती हवाई यात्रा और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) की भूमिका क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक शुरू किए गए नए मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की उक्त योजना के अंतर्गत देशभर में नए गंतव्यों को जोड़ने की कोई योजना है और यदि हां, तो शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और देशभर के दूरस्थ, पर्वतीय और आकांक्षी जिलों को जोड़ने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सिरोही जिले में मानपुर हवाई पट्टी से विमान सेवाएं शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और आरसीएस मार्गों के लिए पाँच दौर की बोली के बाद भी किसी भी एयरलाइन ने बोली प्रस्तुत नहीं की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार को उक्त योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के संबंध में एयरलाइनों और यात्रियों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"आरसीएस-उड़ान की भूमिका" के संबंध में श्री राधेश्याम राठिया और डॉ. हेमांग जोशी द्वारा पूछे गए दिनांक 24 जुलाई, 2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 68 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): नागर विमानन मंत्रालय ने देश के अल्पसेवित और असेवित क्षेत्रों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 21 अक्टूबर, 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) शुरू की है। यह योजना वहनीयता सुनिश्चित करती है चूंकि जिन सीटों पर वीजीएफ प्रदान किया जाता है उनका हवाई किराया सरकार द्वारा निर्धारित किफायती दरों पर सीमित किया जाता है। यह योजना क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालकों को वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करती है, जिसमें शामिल हैं: एयरलाइन प्रचालन लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायतें और योजना के तहत हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए ऐसे मार्गों पर परिचालन लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच के अंतर को कम करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) भी।

योजना के शुरू होने के बाद से, देशभर में 637 आरसीएस मार्गों का प्रचालन शुरू किया गया है, जो 15 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 92 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ते हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों को राष्ट्रीय विमानन मानचित्र में शामिल करके, 'उड़ान' योजना ने यात्रा समय को काफी कम कर दिया है और निवासियों, व्यवसायों दोनों के लिए सुगम्यता बेहतर हुई है तथा पर्यटन में वृद्धि हुयी है।

उड़ान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में विकसित हवाईअड्डों, हेलीपोर्टों और प्रचालित आरसीएस मार्गों का विवरण इस प्रकार है:

छत्तीसगढ़: अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर नामक तीन हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 26 आरसीएस मार्ग।

ओडिशा: जेयपोर, झारसुगुड़ा, उत्केला और राउरकेला नामक चार हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 32 आरसीएस मार्ग।

हिमाचल प्रदेश: शिमला, कुल्लू, रामपुर (एच) और मंडी (एच) नामक चार हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों को जोड़ने वाले 32 आरसीएस मार्ग।

(ग): आरसीएस-उड़ान एक बाजार संचालित योजना है जिसके तहत एयरलाइनों द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए असेवित और अल्पसेवित हवाईपट्टियों/हवाईअड्डों को बोली लगाने के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। इस योजना के तहत और अधिक गंतव्यों और मार्गों को शामिल करने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया के दौर आयोजित किए जाते हैं। विशेष मार्गों पर मांग के आकलन के आधार पर, इच्छुक एयरलाइनें बोली के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। उड़ान 5.2 दौर में, जो विशेष रूप से छोटे विमानों (20 सीटर और उससे कम) के लिए है, स्पिरिट एयर ने 8-सीटर विमान का उपयोग करके शहडोल-भोपाल-शहडोल मार्ग के लिए बोली प्रस्तुत की है।

(घ): बोली प्रक्रिया के पाँच चरणों के दौरान, उत्तर पूर्वी राज्यों में 90 आरसीएस मार्गों का प्रचालन शुरू किया गया है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 12 हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों को जोड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड पहाड़ी राज्यों में 17 हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों को जोड़ते हुए इन दो राज्यों में 92 आरसीएस मार्गों का प्रचालन शुरू किया गया है।

सरकार ने अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू करने की घोषणा की है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए, विशेष रूप से अल्पसेवित और असेवित क्षेत्रों में, यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के ज़िलों में हेलीपैड और छोटे हवाईअड्डों को भी सहायता प्रदान करेगी।

(ङ): जी हाँ, मानपुर हवाईपट्टी उड़ान योजना दस्तावेज़ में असेवित हवाईपट्टियों की सूची में शामिल है। इस योजना के अंतर्गत, सिरोही जिले में मानपुर सहित किसी भी हवाईपट्टी को, किसी भी एयरलाइन द्वारा कनेक्टिविटी के लिए बोली दौर में प्रस्तुत वैध बोलियों के माध्यम से चिह्नित किए जाने पर विकास और प्रचालन के लिए लिया जाता है।

(च): उड़ान योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के संबंध में सरकार को एयरलाइनों और यात्रियों, दोनों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। कुछ प्रमुख चिंताएँ इस प्रकार हैं:

i) शहर के केंद्र से हवाईअड्डे तक अंतिम-छोर संपर्क में चुनौतियाँ।

ii) वीएफआर हवाईअड्डों पर मौसम के कारण कभी-कभी उड़ानों का मार्ग परिवर्तन/रद्द होना।

iii) वीजीएफ अवधि पूरी होने के बाद मार्गों का बंद होना।

iv) गैर-आरसीएस सीटों के कभी-कभी अधिक किराए होना।

******